संख्या-52/2016/481/12-3-2016-100(13)/2014बी

प्रेषक

इन्द्रदेव पटेल**,**
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 30 मार्च, 2016**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 0201-कृषि क्षेत्र की पूॅजीगत योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./677/लेखा-14/15-16, दिनांक 3.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बी.जी.आर.ई.आई. उप योजना में मार्केटिंग सपोर्ट की धनराशि से जनपद सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, चन्दौली, इलाहाबाद एवं बस्ती में निर्मित किये जाने वाले कम्यूनिटी फार्म स्टोरेज बिल्डिंग के निर्माण हेतु रू0-44244 हजार (रू0 चार करोड़ बयालिस लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू**0** में

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग/संस्था का नाम	एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक	अनुमोदित धनराशि	लेखाशीर्षक/मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	Extending green revolution in eastern districts of UP (BGREI)	मण्डी परिषद	18.6.2015	148000	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें-24-वृहद निर्माण कार्य	44244

(रू0 चार करोड़ बयालिस लाख चौवालिस हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर

http://shasanadesh.up.nic.in

वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 7.11.2012 के अनुपालन में मा. मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। आर.के.वी.वाई. की उप योजनाओं में यदि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही लाभार्थियों की पात्रता/अनुदान की धनराशि/मात्रा आदि निर्धारित है तथा इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं है तो ऐसी उप योजनाओं में मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि नियमानुसार आहरित कर कृषि विपणन एवं विशेष व्यापार अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1400/80-1-2013-600(18)/2013, दिनांक 25.7.2013 द्वारा मण्डी स्थलों/उप मण्डलीय स्थलों पर उपलब्ध रिक्त भूमि पर भण्डार गृहों के निर्माण हेतु अधिकृत मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- कम्यूनिटी फार्म स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण जनपद बस्ती हेतु शासनादेश संख्या-448/12-3-2016-100 (13)/2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा, जनपद चन्दौली हेतु शासनादेश संख्या-447/12-3-2016-100(13)/ 2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा, जनपद कौशाम्बी हेतु शासनादेश संख्या-446/12-3-2016-100(13)/2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा, जनपद सिद्धार्थनगर हेतु शासनादेश संख्या-445/12-3-2016-100(13)/2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा, जनपद अम्बेडकरनगर हेतु शासनादेश संख्या-444/12-3-2016-100(13)/2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा एवं जनपद इलाहाबाद हेतु शासनादेश संख्या-443/12-3-2016-100(13)/2014बी, दिनांक 17.3.2016 द्वारा अनुमोदित आगणन के अनुसार ही किया जायेगा। निदेशक, मण्डी द्वारा निर्विविदित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

6- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/ वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

9- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 4401-फसल कृषि कर्म पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0201-कृषि क्षेत्र की पूॅजीगत योजनायें के अन्तर्गत मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

सं**0-481(1)/12-3-2016-**तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई./बी.जी.आर.ई.आई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in